

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री बी०एल०मेहरड़ा, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—182/2018/223 (2018/00182)

1. नारायणसिंह पुत्र उजीरासिंह, जाति रावत, नि० ग्राम मोयणा, तह० मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांत

बनाम

1. श्रीमती मीरा पत्नी किशना, जाति रावत, नि० ग्राम मोयणा, तह० मसूदा, जिला अजमेर ।
2. गाजी पुत्र कम्मा, जाति रावत, निवासी ग्राम मोयणा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।
4. उप पंजीयक, मसूदा, जिला अजमेर ।

रेस्पोंडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, दिनांक 1.6.2018 अंतर्गत वाद संख्या 85/2013.

उपस्थित:—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांत ।
2. रेस्पोंड संख्या 1 व 2 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पोंड संख्या 3 व 4.

निर्णय

दिनांक:—30.4.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोंड संख्या 1/वादी ने अधी०न्याया० में वाद अंतर्गत धारा 53 राज०काश्त०अधि० 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 419 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम मोयणा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके रेस्पोंड संख्या 1/वादिया का 1/3 व रेस्पोंड संख्या 2 का 2/3 हिस्सा संयुक्त रूप से दज्र है । पक्षकारान के मध्य विवादित आराजियात का आदिनांक तक विधिक विभाजन नहीं हो रखा है। अतः उक्त आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे एवं वाद दायरी के बाद किसी भूभाग पर निर्माण किया जाता है तो उसे ध्वस्त कर पूर्व स्थिति लाने का आदेश पारित किया जावे । विद्वान अधी०न्याया० ने अपने निर्णय दिनांक 1.6.2018 द्वारा वादी/रेस्पोंड संख्या 1 का वाद स्वीकार कर प्रारंभिक डिक्री पारित कर वादी/रेस्पोंड संख्या 1 को 2/3 हिस्से का तथा अपीलांत को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश पारित किये । अधी०न्याया० के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांत ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंड को तलब किया गया । रेस्पोंड संख्या 1 एवं 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । अधी०न्याया० का

रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी०न्याया० के समक्ष रेस्प०/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अपीलांट को आदेशिका दिनांक 19.10.2016 के अनुसार पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने के आदेश पारित किये गये थे एवं उसके पश्चात् पत्रावली वास्ते जवाब हेतु अधी०न्याया० में विचाराधीन रही जिसमें दिनांक 1.6.2018 को लोक अदालत के समक्ष पत्रावली को रखा जाकर एक मात्र रेस्प० संख्या 1 की उपस्थिति में वाद को एकपक्षीय रूप से बिना जवाब का अवसर प्रदान किये तथा बिना साक्ष्य लिये दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 1.6.2018 को पारित कर दी जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी०न्याया० के समक्ष रेस्प० संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत कर आराजी खसरा नंबर 419 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा के 1/3 हिस्से के विभाजन हेतु अनुतोष चाहा है एवं रेस्प० संख्या 2 का 2/3 हिस्सा निहित होना वर्णित किया है जिस पर रेस्प० संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार उसके द्वारा 2/3 हिस्से में से 1/3 हिस्से बाबत बेनामा अपीलांट के पक्ष में किया जाकर स्वयं रेस्प० संख्या 1 की उपस्थिति में उक्त आराजी में सड़क के किनारे वाले हिस्से का विभाजन कर सुपुर्द किया जाना एवं सड़क के किनारे वाले 1/3 हिस्से पर अपीलांट का कब्जा होना वर्णित किया है । अपीलांट के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 3.8.2013 में स्पष्ट सीमाओं का अंकन किया हुआ है जिसके अनुसार अपीलांट वापदग्रस्त आराजी पर काबिज है । उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही वादग्रस्त आराजी का बेचान अपीलांट के पक्ष में किया गया है जिसे बिना सुनवाई का अवसर दिये आक्षेपित निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जो विधिविरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । वादी/रेस्प० संख्या 1 ने तथ्य छिपाकर एकतरफा डिक्री पारित करवाई है । अधी०न्याया० ने भी विधिक प्रक्रिया अपनाये एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी०न्याया० का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 1.6.2018 निरस्त की जावे ।
5. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादी/रेस्प० संख्या 1 द्वारा अधी०न्याया० में वाद पत्र पेश किये जाने पर अधी०न्याया० द्वारा प्रतिवादी की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये । दिनांक 19.2.2014 को रेस्प० संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 जा०दी० पेश कर अपीलांट को वादग्रस्त आराजियात का 1/3 हिस्सा बैचान कर मौके पर पूर्व से हो रहे विभाजन के अनुसार कब्जा सुपुर्द किये जाने का निवेदन किया जिस पर अधी०न्याया० द्वारा आदेश दिनांक 19.10.2016 से अपीलांट को पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किये गये तथा इसके उपरांत पत्रावली वास्ते जवाब हेतु विचाराधीन रही किन्तु अधी०न्याया० ने पत्रावली वास्ते जवाब जैरकार रहते पत्रावली का दिनांक 1.6.2018 को लोक अदालत में रखकर रेस्प० संख्या 1/वादी की एकतरफा बहस सुनकर वाद को दिनांक 1.6.2018 को डिक्री कर दिया । अधी०न्याया० की इस कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि अधी०न्याया० ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में वादी/रेस्प० संख्या 1 का वाद डिक्री किया है जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है जहां पक्षकारान

के हित निहित हो वहां पक्षकार को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये किन्तु अधी०न्याया० ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी०न्याया० का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 1.6.2018 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी०न्याया० को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

6. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2018 निरस्त की जाकर प्रकरण अधी०न्याया० को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे अपीलांट को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी०एल०मेहरड़ा)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 30.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी०एल०मेहरड़ा)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर